शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-38 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 18-25 सितम्बर 2023 मूल्य पांच रूपए

वितीय स्थिति पर श्वेत पत्र या पूर्व सरकार पर आरोप पत्र है यह दस्तावेज

- जो लोग फिजूल खर्चों और कुप्रबंधन के लिये जिम्मेदार रहे हैं क्या उनके खिलाफ कोई कारवाई होगी
- क्या वित्त विभाग मंत्रिमण्डल के आगे नतमस्तक हो गया था
- क्या यह श्वेत पत्र और कर्ज लेने की भूमिका है?
- इस श्वेत पत्र को एक ही सरकार के कार्यकाल तक सीमित क्यों रखा गया?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तब प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर जनता को यह कहा था की प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। प्रदेश की जनता से वादा किया था कि वह इस पर श्वेत पत्र जारी करेगी। इस वायदे के अनुसार सरकार ने 46 पन्नों का यह श्वेत पत्र विधानसभा के सामने रखा है। इस पत्र के अनुसार सुक्खू सरकार को 92774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष देनदारियां विरासत में मिली हैं। जिन में 76630 करोड़ की ऋण देनदारी और आरक्षित निधि के तहत जमा हुई 5544 करोड़ की अन्य बकाया देनदारियां और वेतन संशोधन तथा दिसम्बर 2022 तक महंगाई भत्ते की लगभग 10600 करोड़ की बकाया देनदारियां शामिल हैं। 2017-18 के अन्त में यह देनदारियां 47906 करोड़ थी जो 2018-19 से 2022-23 तक बढ़कर 76630 करोड़ पर पहुंच गई है। इन देनदारीयों के कारण आज प्रदेश का हर बच्चा 102818 रुपए के कर्ज तले हैं। श्वेत पत्र के अनुसार प्रदेश की यह स्थिति इसलिए हुई है की जयराम सरकार ने संसाधन बढ़ाने के उपाय न करके केवल कर्ज लेकर ही काम चलाने की नीति पर चलते रहे। दिये गये आंकड़ों के अनुसार अकेले वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12912 करोड़ का ऋण लिया गया जो अब तक एक वर्ष में लिया गया सबसे अधिक कर्ज है।

प्रदेश के 23 सार्वजनिक उपकरणों से 17 घाटे में चल रहे हैं। 31 मार्च 2017 को इनका संचित घाटा 3584.91 करोड़ था जो 31 मार्च 2022 तक बढ़कर 4902.78 करोड़ हो गया। सार्वजनिक उपक्रमों में राज्य विद्युत बोर्ड 1809.61 करोड़ के घाटे के साथ पहले स्थान पर है और एचआरटीसी 1707.12 करोड़ के साथ दूसरे नम्बर पर है। एच.आर.टी. सी. प्रतिमाह 60 करोड़ के घाटे में चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाने से भी प्रदेश को प्रतिवर्ष 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। राजस्व घाटा अनुदान में प्रतिवर्ष केंद्र कमी कर रहा है इससे भी सांसदों संसाधनों में कमी आयी है। इसी तरह जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति बन्द होने से भी राज्य का राजस्व कम हो गया है। इसी के साथ प्रदेश सरकार की उधार लेने की सीमा में भी कटौती करने से भी संसाधनों पर असर पड़ा है। यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि राज्य सरकार केंद्र के पास अपने हितों की ठीक से पैरवी नहीं कर पायी है। इस तरह 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में इस सरकार के पास 6779 करोड़ के संसाधन कम होंगे।

पूर्व की जयराम सरकार कर्ज पर निर्भरता के अतिरिक्त फिजूल खर्ची और दोषपूर्ण नीतियों का भी आरोप है। इसमें इन्वैस्टर मीट पर 27 करोड़ खर्च करके जो आयोजन किये गये और उन में निवेश आने और रोजगार मिलने के जो दावे पेश किये गये थे वह जमीन पर पूरे नहीं हुए। यही नहीं मानकों की अवहेलना करके संस्थाओं का खोला जाना सबसे बड़ी फिजूल खर्ची रही है। प्रशासनिक विभागों ने 584 प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जिनमें से केवल 94 प्रस्तावों को वित्त विभाग की स्वीकृति मिली। स्वास्थ्य विभाग ने 140 प्रस्ताव भेजे जिनमें से सिर्फ नौ को स्वीकृति मिली। शिक्षा विभाग ने 25 प्रस्ताव भेजें और वित विभाग से दो को स्वीकृति मिली। राजस्व विभाग ने 62 प्रस्ताव भेजें और दो को स्वीकृति मिली। यही नहीं कई प्रस्ताव तो वित्त विभाग को भेजे बिना ही सीधे कैबिनेट को भेज दिये गये। शिक्षा विभाग ने 23 महाविद्यालय वित्त विभाग के परामर्श के बिना ही खोल दिये। इसी तरह राजनीतिक कार्यक्रमों आजादी का अमृत महोत्सव और जन मंच कार्यक्रमों पर 6,93,00,238 तथा 534.38 लाख खर्च किये गये। प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों पर 28,42,63,033 रूपये खर्च किये गये। इस तरह पिछली सरकार राजस्व प्राप्तियां में वृद्धि और राजस्व व्यय में वृद्धि के बीच सन्तुलन बनाये रखने में असफल रही। इसके परिणाम स्वरूप राजस्व व्यय में तो 12.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2018-19 में 29442 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 44425 करोड़ हो गया। जबकि इसी अवधि में राजस्व आय 5.77 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30950 करोड़ से बढ़कर केवल 38089 करोड़ ही हो पायी। इसके परिणाम स्वरुप राज्य की वित्तीय स्थिति बिगड़ गयी।

श्वेत पत्र में आये इस विवरण और आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है की पिछली सरकार इस संदर्भ में कतई भी संवेदनशील नहीं रही। न ही डबल इन्जिन की सरकार होने का प्रदेश को कोई लाभ नही मिल पाया है। लेकिन इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी खड़ा होता है कि जब पिछली सरकार यह सब कर रही थी तो प्रशासन क्या कर रहा था। जब वित्त विभाग को नजरअन्दाज करके प्रस्ताव सीधे कैबिनेट को भेज दिये गये तो उस पस वित विभाग ने अपनी आपत्ति क्यों दर्ज नहीं करवाई क्योंकि मंत्रिमंडल की हर बैठक में वित्त विभाग की उपस्थिति अनिवार्य होती है। हर बोर्ड कॉरपोरेशन के संचालक मण्डल में वित्त विभाग का प्रतिनिधि रहता है। यह श्वेत पत्र राजनीतिक नेतृत्व से ज्यादा तो प्रशासन की निष्ठाओं पर सवाल उठाता है। श्वेत पत्र में यह नहीं कहा गया है कि मंत्रिमण्डल ने वित्त और प्रशासनिक विभागों की राय को नजरअन्दाज करके फैसले लिये तथा प्रशासन पर थोपे। क्योंकि यह श्वेत पत्र एक गंभीर आरोप पत्र है जिसमें सरकार पर कुप्रबंधन और फिजूल खर्ची के आरोप लगाये गये हैं। आरक्षित निधि को भी खर्च कर दिया गया जो कि अपने में ही अपराध है। परंतु इन अपराधों के लिये किसी के खिलाफ कोई कारवाई भी की जाएगी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। इस तरह यह श्वेत पत्र एक रस्मअदायगी से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता है। बल्कि आगे के लिये भी ऐसा ही करने का रास्ता खोल देता है। जबकि यहा आना चाहिये था कि जो प्रदेश आज 92774 करोड़ की देनदारीयों पर पहुंच गया है उसमें यह चलन कब और क्यों शुरू हुआ। कर्ज लेकर राहत बांटना कब तक जारी रहेगा। क्योंकि आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं के दाम बढ़ाकर ज्यादा देर संसाधन नहीं जुटाये जा सकते। जनता को महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिये बजटों में की जाने वाली घोषणाओं पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने किया किन्नौर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अपने तीन दिवसीय दौरे के तहत जनजातीय जिला किन्नौर पहुंचे। उन्होंने समदोह के

सैन्य शिविर, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की फारवर्ड पोस्ट लेपचा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। राज्यपाल का जनजातीय जिला किन्नौर का यह पहला दौरा है। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उनके साथ थीं।

राज्यपाल ने 13000 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की फारवर्ड पोस्ट का दौरा भी किया और लेपचा पोस्ट भी गए। नियंत्रण रेखा पर बनी इस पोस्ट से तिब्बत के तीन गांव चुरुप, शकटोट और घुमुर नजर आते हैं। राज्यपाल को सैन्य अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी।

राज्यपाल ने लेपचा में आई.टी.बी.पी. पोस्ट में जवानों के साथ संवाद किया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सीमाओं की रक्षा और देश सेवा के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि आई.टी.बी.पी. के जवान सभी के लिए देश सेवा के प्रति प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक आई.टी.बी.पी. के जवानों के प्रति आदर भाव रखता है।

राज्यपाल ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विभिन्न गांवों का दौरा भी किया।

इससे पूर्व, समदोह हैलीपैड पहुँचने पर ब्रिगेड कमांडर, ब्रिगेडियर आर.पी.सिंह तथा लाहुल-स्पीति तथा किन्नौर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इस अवसर पर आई.टी.बी.पी. के कमांडेंट श्रीपाल ने बल की फ्रंटियर पोस्ट के बारे में अवगत करवाया।

समदोह सैन्य शिविर में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने देवदार का पौधा रोपित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने सैनिकों के साथ बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का उत्साह, जज्बा और देश के लिये समर्पण अदभुत है। हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेठ सेनाओं में शामिल है।

सैन्य शिविर के कमांडर ब्रिगेडियर आर.पी.सिंह ने समदोह में राज्यपाल का स्वागत किया और शिविर के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल और लेडी गवर्नर ने सैन्य शिविर परिसर में देवदार का पौधा भी रोपित किया।

इसके उपरांत सीमावर्ती गांव के लोगों ने राज्यपाल से भेंट की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। राज्यपाल ने कहा कि इस क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा पेयजल योजनाएं व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है।

इस अवसर पर लाहुल-स्पीति के उपायुक्त राहुल कुमार तथा पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने राज्यपाल को सम्मानित किया। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, किन्नौर की उपायुक्त तोरूल एस रवीश, पुलिस अधीक्षक विवेक चाहल तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने साइकिल अभियान को दिखाई हरी झंडी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन से 'पैडल टू

हील हिमालय साइकिल' अभियान को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया।

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) हीलिंग हिमालय के सहयोग से आयोजित इस अभियान में हिमाचल प्रदेश के साइकिल चालक शामिल हैं, जो शिमला से लाहौल-स्पीति तक यात्रा करेंगे।

राज्यपाल ने साइकिल चालकों और हीलिंग हिमालय को बधाई देते हुए कहा कि इस एनजीओ द्वारा हिमालय में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करेगा। उन्होंने हिमालय के पर्यटन क्षेत्र के बारे में जागरूकता के लिए साइकिल चालकों और हीलिंग हिमालय की पहल की सराहना की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की माता ने आपदा राहत कोष में किया अंशदान

शिमला/शैल। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की माता संसार देवी ने आपदा राहत कोष में 50 हजार रुपये का योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सभी क्षेत्रों के लोग उदारतापूर्वक दान देने के लिए आगे आ रहे हैं और उनका नि:स्वार्थ योगदान नि:संदेह प्रदेश के आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक आपदा राहत कोष में 180 करोड़ रुपये से अधिक अंशदान प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस कोष में अंशदान करने वाले सभी व्यक्तियों, सरकारी कर्मचारियों, विभिन्न संगठनों और राज्य सरकारों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक मिसाल पेश करते हुए राज्य में जारी राहत एवं पुनर्वास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए निजी जमापूंजी से 51 लाख रुपये आपदा राहत कोष में दान दिए हैं।

राज्यपाल ने राज्य स्तरीय सायर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोलन जिले के अर्की उपमंडल में आयोजित राज्य स्तरीय सायर मेले के समापन समारोह की

अध्यक्षता करते हुए कहा कि मेले और त्यौहारों के माध्यम से न केवल हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिलता है बल्कि उनका संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि सदियों से चली आ रही परंपराओं को लोगों ने आज भी कायम रखा है।

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से राज्य को भारी नुकसान होने के बावजूद प्रदेश तीव्र गति इस स्थिति से उबर रहा है और अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति इस आपदा में सहयोग देने के लिए आगे आ रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश के लोग बुलंद हौंसले के साथ राज्य के पुनर्निर्माण अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं।

उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सायर मेला लोगों की आस्था से जुड़ा है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास हमारी समृद्ध परंपराओं को संरक्षित करने का होना चाहिए और युवा पीढ़ी को भी संस्कृति से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को हमारी सभ्यता और संस्कृति का न केवल ज्ञान बल्कि उस पर गर्व भी होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा और दुनिया में अपनी पहचान बनायेगा। मेले न केवल सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, बल्कि इनके माध्यम से राज्य की लोक संस्कृति, कला और शिल्प को जानने और समझने का अवसर भी मिलता है।

राज्यपाल ने तीन दिवसीय सायर मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति को बधाई दी। उन्होंने युवा पीढ़ी में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर युवाओं को नशे के प्रवृत्ति से निजात दिलाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

उन्होंने सायर मेले के दौरान आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किये। उन्होंने सायर मेला आयोजन समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया।

राज्यपाल ने सांस्कृतिक संध्या का भी आनंद लिया।

इससे पहले, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने राज्यपाल और लेडी गवर्नर एवं राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा जानकी शुक्ल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सायर मेले का इतिहास लगभग 380 वर्ष पुराना है और यह लोगों की श्रद्धा का केन्द्र है। उन्होंने कहा कि इन उत्सवों के आयोजन से स्थानीय परम्पराओं एवं समृद्ध संस्कृति का संरक्षण होता है। उन्होंने कहा कि त्यौहारों के माध्यम से लोगों के बीच मेल-मिलाप और आपसी भाईचारा बढ़ता है तथा नई ऊर्जा का संचार होता है।

इससे पहले, सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने राज्यपाल का स्वागत किया और सायर मेले के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह, नगर पंचायत अर्की के अध्यक्ष हेमेन्द्र गुप्ता, पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

अभिनेता आमिर खान ने आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपये का अंशदान दिया

शिमला/शैल। हिन्दी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान ने करुणा का परिचय देते हुए आपदा राहत कोष-2023 के लिए 25 लाख रुपये की राशि का अंशदान दिया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आमिर खान के इस सहयोग के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता नि:स्संदेह राहत व पुनर्वास कार्यो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिनका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आपदा से उबरने में मदद करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमिर खान के इस पुनीत कार्य से आपदा प्रभावित लोगों को सहायता मिलेगी।

उप-मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया अंशदान

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति

कर्मचारी संघ की ओर से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 16.73 लाख रुपये की राशि प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि इस तरह के योगदान संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने में सहायक सिद्ध होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में 19 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 24 से 30 अक्तूबर, 2023 तक आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के पूर्वावलोकन (कर्टन रेजर) कार्यक्रम

का शुभारंभ कर इसका ब्रॉशर जारी किया। राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्सव इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्सव के लिए क्षेत्र में निर्बाध परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मंडी-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान प्रदेश विशेषकर कुल्लू जिले में पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद आपदा के दौरान जिला प्रशासन, विभिन्न विभागों, संगठनों एवं लोगों द्वारा राहत एवं पुनर्वास कार्यो के लिए दिया गया योगदान प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक बार फिर पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगामी कुल्लू दशहरा उत्सव इस संबंध में एक मील पत्थर साबित होगा।

पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन प्रदान करने में दशहरा उत्सव की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव वास्तव में एक वैश्विक कार्यक्रम बनने के लिए तैयार है। विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों के साथ-साथ रूस, इजराइल, रोमानिया, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, पनामा, ईरान, मालदीव, मलेशिया, कीनिया, दक्षिण सूडान, जाम्बिया, घाना और इथियोपिया सहित 19 देशों के प्रतिभागी उत्सव में एक विविध और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक झलक दिखायेंगे।

उन्होंने कहा कि उत्सव में 25 अक्तूबर को सांस्कृतिक परेड और 30 अक्तूबर को कुल्लू कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 13 विभाग क्षेत्र की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हुए पैगोड़ा टेंट में प्रदर्शनियां लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके अलावा, उन्होंने सांस्कृतिक एवं लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए उत्सव के दौरान पारंपरिक खेलों और स्थानीय लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले और त्यौहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और इसके प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि कुल्लू दशहरा धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का वैश्विक प्रतीक है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 करोड़ रुपये की कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। जिसमें कुल्लू में 5.49 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित चार मंजिला बहुउद्देशीय उपायुक्त कार्यालय का भवन शामिल है। इस भवन में दो सम्मेलन कक्ष सहित विभिन्न कमरे और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने ढालपुर में उभरती खेल प्रतिभाओं के लिए 3 करोड़ रुपये से निर्मित इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन तथा कुल्लू में 3.51 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महिला पुलिस स्टेशन भी जनता को समर्पित किया।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक भुवनेश्वर गौड़, रवि ठाकुर एवं सुरेंद्र शौरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा , संयुक्त सचिव आईसीसीआर अंजू, उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

ऐतिहासिक बैंटनी कैसल आम जनता के लिए खुला

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक बैंटनी कैसल के हाल ही में जीर्णोद्धार किए गए परिसर का उद्घाटन किया

और कहा कि यह परिसर हमारी संस्कृति और इतिहास का जीवंत प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि बैंटनी कैसल परिसर शिमला की समृद्ध विरासत का साक्षी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी रही 'श्यामला' (शिमला) के समृद्ध इतिहास के दर्शन करवाता है। इस परिसर में तीन ऐतिहासिक भवन हैं और इसके जीर्णोद्धार पर 25 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। लगभग 20,000 वर्ग मीटर में फैला यह परिसर एंग्लो-गॉथिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केन्द्र बनेगा।

उन्होंने कहा कि बैंटनी कैसल परिसर में महात्मा गांधी की शिमला यात्राओं, डॉ.यशवंत सिंह परमार और सत्यानंद स्टोक्स की विस्तृत जीवनियों तथा शिमला शहर के व्यापक इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वालों के प्रति श्रद्धांजलि है। इसमें जनजातीय क्षेत्र स्पीति की समृद्ध संस्कृति को भी प्रदर्शित किया गया है जो क्षेत्र की अनूठी परंपराओं को प्रतिबिंबित करती हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंटनी कैसल परिसर में शिमला के वैभवशाली इतिहास पर आधारित लेज़र लाईट एण्ड साउंड शो भी देखा जिसमें वॉलीवुड के महान अभिनेता अनुपम खेर ने आवाज़ दी है। प्रदेश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता यह शो भावी पीढ़ियों को प्रदेश के समृद्ध इतिहास से अवगत करवाएगा।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (सूचना प्रौद्योगिकी एवं नवाचार) गोकुल बुटेल, विधायक, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने वाघा बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का अवलोकन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के अमृतसर में ऐतिहासिक वाघा बॉर्डर पर भव्य बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का अवलोकन किया।

वाघा बॉर्डर पर प्रत्येक दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान के सुरक्षा बल द्वारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी

का आयोजन किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने देश के कोन-कोने से आये लोगों के साथ इस सेरेमनी का आनंद उठाया।

उन्होंने बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में हिस्सा लेने वाले जवानों को मिठाइयां बांटी और उनके शौर्य और समर्पण की सराहना की।

मुख्यमंत्री अटारी-वाघा बॉर्डर में जीरो पॉइंट पर भी गये।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने आवश्यकता पड़ने पर हर बार अपने प्राणों की आहुति देकर देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण रखा है। उन्होंने कहा कि अपने सैनिकों पर हम सभी को गर्व है।

आई.जी. जालंधर रेंज बी.एस.एफ. व हिमाचल काडर के आई.पी.एस. अधिकारी डॉ. अतुल फुलझेले ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें एक पौधा भेंट किया।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा बड़ी संख्या में देश विदेश के नागरिक उपस्थित थे।

क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण पर बल दिया जाएगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के 9वें

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारम्भ किया। इस फिल्मोत्सव में 20 देशों और भारत के 22 राज्यों के फिल्म निर्माता भाग ले रहे हैं। 24 सितम्बर तक चलने वाले इस महोत्सव में संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, ईरान, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, तुर्की, नेपाल, मिस्र, बांग्लादेश, इटली, पोलैंड, अर्जेंटीना, स्वीडन, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, फ्रांस और दुबई के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता अपनी फिल्मों को प्रदर्शित करेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव 20 देशों और पूरे भारत की संस्कृति, मूल्यों और कला का समागम है। उन्होंने कहा कि समाज को प्रतिबिम्बित करने में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्हें जब अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय मिलता है तो वह अवश्य फिल्में देखते हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन की व्यस्ताओं में फिल्में मनोरंजन उपलब्ध करवाने का एक साधन है। उन्होंने सिनेमा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि फिल्में एक दर्पण के रूप में कार्य करती हैं, जो समाज की विविधता, संस्कृति और मुद्दों को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पहाड़ी भाषा और क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि शिमला का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जो हिमाचल प्रदेश और वैश्विक फिल्म समुदाय के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम रखता है। सिनेमा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, सिद्धांतों और कला को दुनिया तक पहुंचाते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव पुस्तिका का विमोचन भी किया। उन्होंने महोत्सव के शुभारम्भ के दौरान प्रदर्शित फिल्म 'रोया' भी देखी।

महोत्सव के निदेशक पुष्प राज ठाकुर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया करते हुए कहा कि इस वर्ष 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिमला के अंतर्गत कण्डा और नाहन की म डल सेंट्रल जेल में भी फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ढली में विशेष योग्यता वाले बच्चों के संस्थान में भी फिल्में दिखाई जाएंगी। यहां पर 130 छात्रों को अपने परिसर में फिल्में देखने का अवसर मिलेगा। शिमला के गेयटी थिएटर के साथ इन स्थानों में 22 से 24 सितंबर, 2023 तक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी की जाएगी।

मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, सुरेश कुमार, राजेश धर्माणी, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, निदेशक भाषा, कला एवं संस्कृति पंकज ललित, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क राजीव कुमार, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो । और हर दुसरे विचार को अपनी ज़िन्दगी से निकाल दो यही सफ़लता की कुंजी है । ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

संविधान की प्रस्तावना से गायब हुए धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद

संसद का विशेष सत्र पुराने भवन में शुरू हुआ और दूसरे ही दिन नये भवन में चला गया। नये भवन में जब सांसदों ने प्रवेश किया तो उन्हें देश के संविधान की एक-एक प्रति दी गयी। संविधान की प्रति को जब खोल कर देखा गया तो उसकी प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द गायब मिले। कुछ सांसदों ने जब इस ओर इंगित किया तो जवाब मिला कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मूल प्रतिवेदन में जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उसमें इन शब्दों का उल्लेख नहीं है। यह शब्द आपातकाल के दौरान 1976 में लाये गये 42वें संविधान संशोधन से इसमें जोड़ गये हैं। नये संसद भवन में प्रवेश से पहले जो जी-20 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें राष्ट्रपति की ओर से आयोजित राजकीय भोज के जो आमंत्रण पत्र सामने आये थे तो उनमें भी इण्डिया के राष्ट्रपति की जगह भारत का राष्ट्रपति लिखा हुआ था। शब्दों के इस चयन से इण्डिया बनाम भारत का विवाद अनचाहे ही खड़ा हो गया। इसी दौरान सनातन धर्म को लेकरआयी टिप्पणियों पर प्रधानमंत्री ने जिस तर्ज पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपने सहयोगी मंत्रियों को इसका कड़ा विरोध करने के निर्देश दिये हैं उससे भी कुछ अलग ही संकेत उभरते हैं।

इसी परिदृश्य में हुए संसद के विशेष सत्र को लेकर जो जो क्यास लगाये जा रहे थे उन सबसे हटकर अन्त में महिला आरक्षण विधेयक सामने आया है। इसमें महिलाओं को संसद और राज्यों की विधानसभाओं में 33% स्थान आरक्षित रखने की सिफारिश की गयी है। संसद के दोनों सदनों में यह विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया है। किसी भी दल ने इसका विरोध नहीं किया है। बल्कि इसमें अन्य पिछड़े वर्गो और मुस्लिम महिलाओं को भी इस संशोधन का लाभार्थी बनाने की मांग की है। मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाने और ओ बी सी समाज की बदनामी के मुद्दे पर राहुल गांधी की सांसदी छीनने वाली सरकार इन वर्गो की महिलाओं को इस आरक्षण के दायरे में क्यों नहीं ला पायी यह सवाल अपने में गंभीर हो जाता है। यह महिला आरक्षण आने वाले लोकसभा चुनाव में लागू नहीं होगा क्योंकि इससे पहले जन गणना और फिर परिसीमन आयोग बैठेंगे। ऐसे में यह सवाल भी प्रमुख हो जाता है की जो प्रावधान अभी लागू ही नही होना है उसे विशेष सत्र बुलाकर पारित करने का औचित्य क्या है? फिर इस में ओ बी सी और मुस्लिम समाज को लेकर जो सवाल खड़े हो गये हैं उनका निराकरण किया जाना भी आवश्यक होगा जो आने वाले समय का बड़ा सवाल होगा।

इस परिप्रेक्ष में यदि इस सब को इकट्ठा मिलाकर देखें तो साफ दिखाई देता है कि आने वाले चुनावों में नये मुद्दे उछालने के लिये ही इण्डिया बनाम भारत और सनातन की रक्षा करने जैसे विषय खड़े करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। क्योंकि इण्डिया से भारत करने और संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटाने के लिये संविधान संशोधनों का मार्ग अपनाने की जगह जो यह भावनात्मक कार्ड उभारने का प्रयास किया गया है इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। इस आशंका की पुष्टि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के उस वीडियो से हो जाती है जिसमें वह यह कह रही हैं कि आने वाला चुनाव धर्म और अधर्म के बीच होगा। इसी विशेष सत्र में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिये सदन के पटल पर जिस भाषा और तर्ज का इस्तेमाल किया है उसके मायने भी कुछ स्मृति ईरानी के वक्तव्य की ही पुष्टि करते हैं।

राष्ट्रीय हितों को लेकर संवेदनशील है मोदी सरकार, ट्रूडो व बाइडेन के ब्यान पूर्वाग्रह से ग्रस्त

गौतम चौधरी

भारत की अध्यक्षता में संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन 2023 की समीक्षा हो रही थी कि दुनिया के दो प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने अपने ब्यानों से इस कार्यक्रम को नकारात्मक स्वरूप देने क कोशिश की। इन दो राष्ट्रध्यक्षों में पहले स्थान पर हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दूसरे, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। जी20 शिखर सम्मेलन के बाद जस्टिन ने भारत पर आरोप लगाया कि उसके यहां ब्रिटिश कोलंबिता में मारे गए खालिस्तान समर्थक चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जी 20 शिखर सम्मेलन के बाद वियतनाम की आधिकारिक यात्रा में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, ''उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान 'मानवाधिकारों का सम्मान' और 'स्वतंत्र प्रेस' का मुद्दा उठाया था।'' भारत ने इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के ब्यानों को सिरे से खारिज कर दिया है।

भारत की वर्तमान सरकार जिस प्रकार अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर आक्रामक है वैसा अतीत में बहुत कम देखने को मिलता है। कई मामलों में श्रीमती इंदिरा गांधी आक्रामक थी लेकिन पश्चिम दबाव के कारण उसकी आक्रामकता थोड़ी कमजोर पड़ जाती थी लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपने राष्ट्रीय हितों के प्रति बेहद संवेदनशी है। यह सरकार ऐसा कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिती, जिसमें राष्ट्रीय हित सन्निहित है।

अमेरिका और पश्चिमी जमात लबे समय से कुछ पूर्वाग्रह पाले हुए है। उस पूर्वाग्रह के कारण पश्चिमी ताकत कभी रूस तो कभी चीन के खिलाफ मोर्चा खोतली रहती है। वर्तमान परिस्थिति बदल चुकी है। वर्तमान दौर में चीन ने अपने तरीके से इनके खिलाफ मोर्चा खोला है। उस मोर्चे में रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इन देशों के समूह ब्रिक्स ने व्यापार, वित्त, विज्ञान, तकनीक और कूटनीति की दिशा बदल दी है। यही नहीं चीन के द्वारा स्थापित शंघाई सहयोग संगठन, अमेरिकी नेतृत्व में स्थापित नाटो को मात देने लगा है। इसके कारण पूरा पश्चिमी जमात सकते में है।

अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकार हनन की बात कर रहे हैं। यही नहीं बाइडेन के मंत्री और कूटनीतिक, भारत के खिलाफ मीडिया युद्ध में जमकर हिस्सा भी ले रहे हैं। यदि सचमुच अमेरिका मानवाधिकार समर्थक है तो वह अपने देश में हो रहे काले लोगों के खिलाफ अपराध को रोकने में नाकाम क्यों है? सवाल यहां खत्म नहीं होता है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया में जितने अपराध किए हैं, उतना आजतक किसी देश ने नहीं किया। मानवाधिकार की दुहाई देने वाला अमेरिका अपने मित्र देशों के अपराध पर सदा से रहस्यमय चुप्पी साधे रहा है। खुद अमेरिका ने बिना किसी प्रमाण के इराक व लिबिया पर जैविक व राशायनिक हथियार होने का आरोप लगा हमला किया और लाखों निर्दोष नारिकों की हत्या की। जापान के दो बड़े शहरों पर परमाणु बम गिराकर उसे इस तरह तबाह कर दिया कि आज भी वहां शारिरिक व मानसिक रूप से अक्षम बच्चे पैदा हो रहे हैं। जी20 शिखर सम्मेलन के बाद जिस वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर जो बाइडेन गए, वहां के निर्दोष नागरिकों पर अमेरिका ने ऐसा कहर ढ़ाया था, जिससे मानवता शर्मसार हो जाये। वहीं अमेरिका अब भारत को मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ा रहा है।

जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की सुरक्षा कमजोरी का ठिकड़ा भारत पर फोड़ने की कोशिश की है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सिख नेता और खालिस्तान समर्थक 45 वर्षीय हरदीप सिंह निज्जर की इसी वर्ष 18 जून को हत्या कर दी गयी। ट्रूडो की निंद तब खुल रही है जब जी20 का सम्मेलन होता है। इससे पहले न तो उनके पास कोई खुफिया इनपुट था और न ही कोई जानकारी। कनाडा में रह रहे लोगों की सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रहे ट्रूडो अपनी असफलता को भारत के माथ्थे मढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि विगत कई वर्षो से ट्रूडो और उनके सहयोगी खालिस्तान समर्थक आन्दोलन को हवा दे रहे हैं। यदि खालिस्तान से ट्रूडो को इतना ही प्रेस है तो वे अपने देश का एक हिस्सा बांट कर खालिस्तान नामक स्वतंत्र देश बना दें। ऐसा करने पर दुनिया का पहला देश भारत होगा जो उस खालिस्तान को मान्यता प्रदान करेगा।

ट्रूडो न तो अपने देश के नागरिकों की चिंता है और ही दुनिया में शांति की चिंता है। ट्रूडो उस आग से खेल रहे हैं, जो अंततोगत्वा उनके लिए ही परेशानी खड़ी करेगा। भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध व कटिबद्ध है। हर राष्ट्र को अपनी सीमा और नागरिकों की रक्षा का अधिकार है। ट्रूडो भारत को उससे रोक नहीं सकते हैं। उनका आरोप यदि सही है तो वे प्रमाण लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाये। यदि उनके पास प्रमाण नहीं है तो वे भारत से माफी मांगे। हालांकि उनका एजेंडा सिखों की सुरक्षा का कतई नहीं है। वे तो भारत को महज बदनाम करना चाहते हैं। साथ ही सिखों को यह दिखाना चाहते हैं कनाडा का प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यदि वे सचमुच में सिखों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील होते तो निज्जर के असल हत्यारे अब तक पकड़े गये होते।

कुल मिलाकर अमेरिका व कनाडा के राष्ट्राध्यक्षों के ब्यानों को पूर्वाग्रही सोच का नतीजा ही समझा जाना चाहिए। साथ ही इससे यह भी साबित होता है कि भारत की ताकत बढ़ रही है और रूस, चीन के बाद भारत पश्चिम के लिए चुनौती बन कर खड़ा होने स्थिति में आ गया है। इन ब्यानों और गतिविधियों से भारतीय कूटनीति को न तो कोई धक्का लगेगा और न ही इसका दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। भारत में निवास करने वाले सिख अच्छी तरह भारतीय राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए हैं। मुठी कर चरमपंथी आम सिखों की राय नहीं बन सकते। आतंकवाद ने पंजाब और सिख दोनों को परेशान किया है। ट्रूडो चाहे जितना जोर लगा लें पंजाब में अब आतंकवाद का दौर लौटने वाला नहीं है। क्योंकि पंजाब और सिखों को आतंकवाद की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। दूसरी बात ट्रूडो याद रखें, जिस प्रकार इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन करने के कारण पाकिस्तान परेशान हुआ, उसी प्रकार कनाडा को भी इसकी कीमत चुकानी होगी।

एक तारीख एक घंटा एक साथ

1 अक्तूबर 2023 को सुबह 10 बजे नागरिकों के नेतृत्व में स्वच्छता के लिए एक घंटे के श्रमदान का राष्ट्रीय आह्वान

शिमला। 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छता के लिए एक स्पष्ट संदेश देकर आहवान किया था। सभी क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों ने इसका स्वागत किया और सक्रियता दिखाते हुए स्वच्छ भारत के लिए स्वामित्व लेने में अत्यधिक उत्साह दिखाया। परिणामस्वरूप स्वच्छता एक राष्ट्रीय स्वभाव परिवर्तन बन गया और हर किसी की जुबान पर स्वच्छ भारत मिशन एक घरेलू नाम की तरह बन गया। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 1 अक्तूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील की, जो गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ही बापू को 'स्वच्छांजलि' होगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा,1 अक्तूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आप भी समय निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में सहयोग करें। आप भी अपनी गली, आस-पड़ोस... किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर इस स्वच्छता अभियान में शामिल हो सकते हैं।

अपने आस-पड़ोस से लेकर रेलवे ट्रैक तक, धार्मिक स्थानों से लेकर राजमार्गो तक, सार्वजनिक स्थानों से लेकर घरों तक, अब कचरा मुक्त भारत का समय है। हर स्थानीय शहरी निकाय और ग्राम पंचायत सफाई अभियान के लिए जगह का चयन करेगी। ये सभी स्थल एक मानचित्र पर उपलब्ध होंगे जिन्हें सभी नागरिक स्वच्छता ही सेवा-सिटिजन पोर्टल https://swachhatahiseva.com/ पर उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से देख और चुन पाएंगे। NGO@ RWA और निजी संगठन आदि जो सफाई कार्यक्रम आयोजित करने के इच्छुक हों, वे भी यूएलबी/जिला प्रशासन, जो भी हो, इसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अनुमति मिलने के बाद वे सभी नए इवेंट क्रिएट कर पाएंगे। गतिविधि के समापन के बाद इवेंट क्रिएट करने वाले संगठनों को कार्यक्रम में हुई भागीदारी और उसके मुख्य अंश आदि का विवरण देना होगा। सफाई अभियान स्थल पर ही लोग अपने फोटो क्लिक कर इसी पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें आधिकारिक हैशटैग: #SwachhBharat, #SwachhataHiSeva और हैंडल्स @SwachhBharatGov, @swachhbharat इत्यादि के साथ सोशल मीडिया पर भी साझा कर सकेंगे। स्वच्छता ही सेवा पोर्टल पर नागरिकों और इन्फ्लूएंसर्स को पखवाड़े से जुड़ने और स्वच्छता दूत बनने का निमंत्रण देने का भी प्रावधान है।

स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल के उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्तूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा-स्वच्छता ही सेवा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस पखवाड़े में पुरानी इमारतों की मरम्मत से ले कर जल-निकायों की सफाई, घाटों की सफाई से ले कर दीवारों को रंगने, नुक्कड़ नाटकों से ले कर रंगोली प्रतियोगिताओं जैसे सभी काम हो रहे हैं। पखवाड़े के उद्घाटन से ले कर अब तक स्वच्छता ही सेवा अभियान से 5 करोड़ से भी अधिक नागरिक जुड़ चुके हैं।

पीएम विश्वकर्मा योजना के दिशानिर्देश

शिमला। प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर, 2023 को केंद्रीय पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में 18 व्यवसायों जैसे (i) बढ़ई, (ii) नाव निर्माता, (iii) हथियार निर्माता, (iv) लोहार, (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता, (vi) ताला बनाने वाला, (vii) सोनार, (viii) कुम्हार (ix) मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाला), पत्थर तोड़ने वाला, (x) मोची/जूता कारीगर, (xi) राजमिस्त्री, (xii) टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकरए (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक) (xiv) नाई (xv) माला बनाने वाला (xvi) धोबी (xvii) दर्जी और (xviii) मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है

(i) पहचान: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान।

(ii) कौशल उन्नयन: 500 रुपये प्रति दिन के वजीफे के साथ 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण।

(iii) टूलकिट प्रोत्साहन: बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रु. रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।

(iv) कर्ज सहायता: बिना कुछ गिरवी रखे 'उद्यम विकास ऋण' के रूप में तीन लाख रुपए तक का ऋण एक लाख और दो लाख रुपए के दो किश्तों में क्रमश: 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8 प्रतिशत की सीमा तक छूट के साथ प्रदान किया जाएगा । जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे एक लाख रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किश्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दूसरी ऋण किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का लाभ उठाया है और एक मानक ऋण खाता बनाये रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

(v) डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेनदेन एक रुपये की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेनदेन मासिक तक लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।

(vi) विपणन सहायता: मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार के लिए कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर मौजूदगी, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।

उपयुक्त लाभों के अलावा, यह योजना लाभार्थियों को औपचारिक एमएसएमई परितंत्र में 'उद्यमियों' के रूप में उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर शामिल करेगी।

लाभार्थियों का नामांकन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों के नामांकन के बाद तीन-चरणों में सत्यापन किया जाएगा जिसमें (i) ग्राम पंचायत/यूएलबी स्तर पर सत्यापन, (ii) जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जांच और सिफारिश (iii) स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन शामिल होगा।

अधिक जानकारी के लिए पीएम विश्वकर्मा के दिशानिर्देश pmvishwakarma.gov.in पर देखे जा सकते हैं। योजना के संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, कारीगर और शिल्पकार 18002677777 पर कॉल कर सकते हैं या pm-vishwakarma@dcmsme .gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

नशा मुक्त भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

शिमला। मादक द्रव्य के उपयोग से जुड़ी नशे की लत एक ऐसा मुद्दा है जो देश के सामाजिक ताने-बाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। किसी भी पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उनके परिवारों और पूरे समाज को भी प्रभावित करती है। विभिन्न साइको-एक्टिव पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति इन पर निर्भर हो जाता है।

राष्ट्रीय औषधि निर्भरता उपचार केंद्र (एनडीडीटीसी), एम्स, नई दिल्ली के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा भारत में मादक द्रव्यों के उफपयोग की सीमा और पैटर्न पर पहले व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, शराब भारतीयों द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम साइको-एक्टिव पदार्थ है। इसके बाद कैनबिस और ओपियोइड्स आते हैं।

नशीली दवाओं की मांग के खतरे को रोकने के लिए, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रहा है, जो एक व्यापक योजना है जिसके तहत राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र (यूटी) प्रशासन को निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पूर्व-नशीले पदार्थों के आदी लोगों की आजीविका सहायता आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2020 से, मंत्रालय उच्च शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों, स्कूलों और समुदाय तक पहुंच बनाकर और अभियान में सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व हासिल करके युवाओं पर विशेष ध्यान देते हुए मादक द्रव्यों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। इसी उद्देश्य से देश के सभी जिलों में महत्वाकांक्षी नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) लागू किया जा रहा है।

इस लत से निजात पाने के लिए एनएमबीए अहम भूमिका निभा रहा है। अब तक नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अब तक 11 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। चिन्हित जिलों में अभियान गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए 8,000 मास्टर स्वयंसेवकों का चयन और प्रशिक्षण किया गया है। 3.36 करोड़ से अधिक युवाओं ने अभियान की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है और मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ संदेश फैलाया है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, महिला मंडलों और महिला एसएचजी के माध्यम से बड़े समुदाय तक पहुंचने में 2.24 करोड़ से अधिक महिलाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल बनाकर और उन पर दैनिक अपडेट साझा करके अभियान के संदेश को ऑनलाइन फैलाने के लिए प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है। जिलों और मास्टर स्वयंसेवकों द्वारा रियल टाइम पर जमीन पर होने वाली गतिविधियों के डेटा को कैप्चर करने के लिए एक एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। जनता की पहुंच में आसानी के लिए सभी नशामुक्ति सुविधाओं को जियो-टैग किया गया है।

एनएमबीए के तहत एक विशेष पहल एक ऐसा प्रयास है जिसमें विभिन्न गतिविधियों को चलाने और उनके बैनर तले एनएमबीए के संदेश को फैलाने के लिए धार्मिक/आध्यात्मिक संगठनों का सहयोग है। इस दिशा में एक कदम उठाते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने युवाओं, महिलाओं, छात्रों और समुदाय के बीच एनएमबीए का संदेश फैलाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (एचएमएसजेई) ने देश में नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किए गए प्रयासों के बारे में बात की, जिसने इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने में मदद की है। मंत्री ने सभा को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, रक्षा मंत्री की उपस्थिति में एनसीसी इंटरेक्शन जैसे विशेष आयोजनों के बारे में जानकारी दी, जो नशीली दवाओं के उपयोग के खिलाफ अभियान में हितधारकों को शामिल करने के लिए नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इस अभियान में आध्यात्मिक संगठनों की भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए, मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि गायत्री परिवार के साथ यह सहयोग व्यक्तियों के जीवन को रोशन करने और उन्हें नशे की राह पर जाने से रोकने के साथ साथ एक मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत समाज के निर्माण में काफी मदद करेगा।

अखिल विश्व गायत्री परिवार के डॉ.चिन्मय पंडड्या ने नशे के खिलाफ इतना व्यापक अभियान शुरू करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को बधाई दी। इस क्षेत्र में काम करने के अपने अनुभवों के माध्यम से, उन्होंने एक अनुकूल पारिवारिक और सामाजिक वातावरण के महत्व पर जोर दिया जो मादक द्रव्यों के उपयोग को रोकने के साथ-साथ उस पर काबू पाने में भी मदद करेगा। डॉ. पंडड्या ने अखिल विश्व गायत्री परिवार से जुड़े 5000 केंद्रों और 16 करोड़ से अधिक लोगों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान में भागीदारी और नशा मुक्त भारत में योगदान की पुष्टि की।

इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को लगता है कि एनएमबीए के कार्यान्वयन से भारत को दवा के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सौरभ गर्ग ने कार्यक्रम में भाग लिया और संबोधित किया।

हिमाचल में बढ़ रहा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, सरकार ने किया एसआईटी का गठन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित करने का एलान किया है। आईपीएस अधिकारी अभिषेक दुल्लर की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया जाएगा। अभिषेक दुल्लर मौजूदा समय में डीआईजी नॉर्दन रेंज के पद पर है और वह लंबे समय तक सीबीआई में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यह कमेटी पूरे प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी मामले में जो शिकायतें आयी है या किसी के साथ फ्रॉड हुआ है उसकी जांच करेगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में देहरा के विधायक होशियार सिंह के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले पूरे प्रदेश में आये हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का फ्राड पूरे देश में हो रहा है। जो लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने की चाह रखते हैं वह बहुत जल्दी इसके झांसे में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड मामले के छह एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। जबकि 56 शिकायतें पुलिस के पास इसको लेकर आयी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में कारवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एसआईटी में ऐसे अधिकारियों को शामिल करेगी जो इस तरह के मामलों की जांच के लिए निपुण हो। उन्होंने कहा कि विधायक होशियार सिंह ने जो सवाल उठाया है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ का फ्रॉड हुआ है उस पर अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मामले की जांच हो।

इससे पहले विधायक होशियार सिंह ने अनुपूरक सवाल में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र देहरा में ही 10 करोड़ का फ्रॉड किया गया है। उन्होंने सदन में 425 लोगों की सूची भी रखी जिन्होंने यह फ्रॉड किया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाये ताकि गरीब लोगों का पैसा लूटने से बचाया जा सकें।

विधायक होशियार सिंह ने सदन में कहा कि यह स्कैम करोड़ों में है। 200 करोड़ का स्कैम हमीरपुर में हुआ है, 250 करोड़ का कांगड़ा, 100 करोड़ का ऊना में फ्रॉड किया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण से यह फ्रॉड किया गया है। उन्होंने कुछ कंपनियों के नाम भी बताये। उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा स्कैम नहीं हो सकता। उन्होंने अपने विस क्षेत्रों का जिक्र करते हुये कहा कि फ्रॉड करने वाले ये लोग राजनीतिज्ञों के साथ देखे जाते हैं। राजनीतिक संरक्षण व दबदबे के साथ फ्रॉड करते हैं और प्रदेश की भोली भाली जनता को ठगा जाता है। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि इस फ्राड में राजनीतिक संरक्षण की बात सामने नहीं आयी है।

भाजपा शासन में अमृत महोत्सव के आयोजन पर हुए छह करोड़ 93 लाख खर्च

शिमला/शैल। हिमाचल विधानसभा के शिमला में चल रहे मानसून सत्र के प्रश्नकाल में अमृत महोत्सव के आयोजन का मुद्दा गूंजा। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षो में भाजपा शासन के दौरान अमृत महोत्सव के आयोजन में छह करोड़ 93 लाख रूपये खर्च किए गए। यह कार्यक्रम अमृत महोत्सव देश की आजादी के 75 पूर्व पूरा होने के उपलक्ष्य केंद्र की योजना के तहत मनाया गया। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है, लेकिन इसके लिए प्रदेश से बजट खर्चा गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम उन लोगों के लिए समर्पित होने चाहिए, जिन्होंने देश को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाया। लेकिन प्रदेश में हुए इन कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सैनानियों के परिवारों को नहीं बुलाया गया। पूर्व सरकार इस तरह के आयोजन में स्वतंत्रता सैनानियों को बुलाकर उनका सम्मान करती तो इस समारोह की महत्वता और ज्यादा होती। इसे राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भविष्य में इस तरह के आयोजन को बंद नहीं करेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे कार्यक्रमों में स्वतंत्रता सैनानियों को बुलाया जाये।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अमृत महोत्सव के कार्यक्रम देश भर में मनाये गये। लेकिन वर्तमान सरकार इस कार्यक्रम में हुए खर्चो को मुद्दा बना रही है। यह केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम था, जो देश भर में मनाया गया। इस दृष्टि से हिमाचल में भी इसका आयोजन हुआ और इसमें खर्चा हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार में इसके आयोजन में किसी स्थान पर स्वतंत्रता सैनानियों के परिवारों को न बुलाना एक त्रुटि हो सकती है और इसमें सुधार होना चाहिए। उन्होंने अनुपूरक सवाल में जानना चाहा कि सरकार स्पष्ट करे कि अगर केंद्र का कोई कार्यक्रम या योजना आती है तो क्या उसे राज्य सरकार प्रदेश में लागू नहीं करेगी। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से निरस्त लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना को बहाल करने की भी मांग की।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना को जरूरत के आधार पर मनाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके आयोजन में स्वतंत्रता सैनानियों के परिवारों को बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक संजय रत्न स्वतंत्रता सैनानी के परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्हें भी इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया।

इससे पहले विधायक संजय रत्न ने कहा कि ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दृष्टिगत अमृत महोत्सव मनाया और इसके आयोजन में सरकारी राशि का दुरूपयोग हुआ। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर हुए इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सैनानियों के परिजनों को नहीं बुलाया गया। उनके हल्के में हुए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनावी मकसद से इन कार्यक्रमों को आयोजन किया। इसमें बड़े पैमाने पर सरकारी धनराशि का दुरूपयोग हुआ है। बेहतर तो यह होता कि पूर्व सरकार अमृत महोत्सव के आयोजन पर धनराशि खर्च करने की बजाय स्वतंत्रता सैनानियों के सम्मान में शहीद स्मारकों का निर्माण करती।

हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में आठ विधेयक पारित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के समापन भाषण में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कहा कि मानसून सत्र की कुल सात बैठकें हुई और 36 घंटे 38 मिनट सदन की कार्यवाही चली। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 106 फीसदी रही।

पठानिया ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान कुल 369 तारांकित और 186 अतारांकित प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा नियम-61 के तहत आठ, नियम-62 के तहत पांच और नियम-130 में तीन विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान एक दिन गैरसरकारी दिवस में सदस्यों ने नियम-101 के तहत तीन गैरसरकारी संकल्प प्रस्तुत किये गये। इनमें एक संकल्प पिछले बजट सत्र का था, जबकि एक संकल्प का उत्तर अगले सत्र में होगा।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि नियम-102 के तहत मानसून से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा मानते हुए 12 हजार करोड़ के पैकेज संबंधी सरकारी संकल्प सार्थक चर्चा के बाद पारित किया गया। इस संकल्प पर तीन दिन तक चर्चा चली, जिसमें सतापक्ष के 27, विपक्ष के 21 और तीन निर्दलीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस संकल्प पर 15 घंटे 30 मिनट तक चर्चा चली। इस सत्र के दौरान आठ विधेयकों को पुर्नस्थापित व पारित किया गया, जबकि एक विधेयक संशोधित रूप से पारित हुआ। सत्र में सदन के नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पांच घंटे जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दो घंटे 48 मिनट तक बोले। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सुचारू संचालन के लिए मुख्यमुंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आभार जताया।

सत्र के समापन के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नाचन के भाजपा विधायक के खिलाफ दर्ज मामले को खत्म करने की मांग की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये परंपरा बन जाएगी और विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर विचार करेगी। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सरकार द्वारा लाए गए श्वेतपत्र पर भी हैरानी जताई और कहा कि श्वेतपत्र में कई ऐसे मुद्दे डाले गये हैं, जो सिर्फ केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सत्र के दौरान कई सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं थे।

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 15वें वितआयोग के समक्ष अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा है, जिससे प्रदेश को केंद्र से मिलने वाली मदद में भारी कमी आयी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा घटाई है और जीएसटी के तह मिलने वाला मुआजा भी बंद किया है जिससे प्रदेश की माली हालत और बिगड़ी है। उन्होने विपक्ष द्वारा प्रदेश में आई आपदा को लेकर पारित संकल्प के दौरान खमोश रहने पर भी हैरानी जताई और कहा कि भाजपा अब इस संकल्प के माध्यम से केंद से मांगी गई 12 हजार करोड की मदद को दिलाकर अपनी गलतियों को सुधार सकती है।

शिमला से शिफ्ट नहीं होंगे सरकारी दफ्तर

शिमला/शैल। प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व की सुक्खू सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी शिमला से कोई भी सरकारी दफ्तर प्रदेश से बाहर शिफ्ट नहीं होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि शिमला शहर में स्थित विभागों के मुख्यालयों व निदेशालयों को प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने बारे सरकारी स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव किसी विभाग से प्राप्त हुआ है।

शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने सवाल किया था कि वर्तमान में शिमला शहर बहुत अधिक भीड़-भाड़ वाला हो चुका है और मानसून में भारी वर्षा के कारण शहर में जान-माल का नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए क्या सरकार शिमला शहर में स्थित विभागों के मुख्यालयों व निदेशालयों को प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतिर करने का विचार रखती है।

शराब ठेकों की नीलामी से 40 फीसदी बढ़ा सरकार का राजस्वः उपमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने शराब ठेकों की नीलामी से अपना राजस्व बढ़ाया है। राज्य सरकार ने आबकारी नीति के तहत ऑक्शन कम टेंडर के माध्यम से 1815 करोड़ में शराब के ठेकों का आबंटन किया है। इसमें से 1301 करोड़ सरकारी खजाने में आ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में यह जानकारी सदन में दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष यानि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1296.94 करोड़ में ठेकों को नीलाम किया गया था। इस साल सरकार ने ऑक्शन कम टैंडर के आधार पर जो नीलामी का निर्णय लिया। सरकार के इस पारदर्शी कदम से 39.97 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 में शराब के ठेकों का आबंटन नवीनीकरण द्वारा किया गया था। जबकि इस साल ऑक्शन कम टैंडर के माध्यम से किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 518.41 करोड़ अधिक है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस वितीय वर्ष में ठेकों की नीलामी से अभी तक 1301 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। यह राशि सरकारी कोष में जमा हो चुकी है। 21 प्रतिशत की ग्रोथ अभी तक हो चुकी है, और जो तय लक्ष्य है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा।

एक जनवरी से 31 अगस्त तक प्रदेश में साइबर क्राइम के 49 मामले दर्ज

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ रहा है। इस साल साइबर अपराध के मामलों में बढ़ौतरी देखी गई है। हर महीने औसतन साइबर अपराध से जुड़े आठ मामले सामने आ रहे हैं। विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में इस साल एक जनवरी से 31 अगस्त तक साइबर अपराध के 49 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार गंभीर है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मंडी, धर्मशाला और शिमला में रेंज स्तर पर तीन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले हैं। इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 भी खोला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करने पर भी बल दिया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नए स्कैम और फ्रॉडस के बारे सोशल मीडिया पेज पर एडवाइजरी जारी की जाती है।

प्रदेश में एमबीबीएस डॉक्टरों के 64 पद खाली

शिमला/शैल। प्रदेश के अस्पतालों में एमबीबीएस डॉक्टरों के 64 पद खाली हैं। प्रदेश भर में एमबीबीएस डॉक्टरों के 2802 पद स्वीकृत हैं। इनमें 2738 पद भरे गए हैं, जबकि शेष 64 रिक्त हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 580 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 104 सामुदायिक केंद्र, तीन जोनल अस्पताल, नौ क्षेत्रीय अस्पताल, 92 नागरिक अस्पताल और छह मेडिकल कालेज हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्पैशलिस्ट डॉक्टरों के लिए अगल से कैडर बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग प्री–वर्ल्ड कप के लिए वेबसाइट और प्रोमो जारी किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के बीड़-बिलिंग में 26 अक्तूबर, 2023 से आयोजित होने वाले क्रॉस कंट्री

पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप-2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और प्रोमो जारी किया।

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 28 देशों के 159 प्रतिभागियों ने पहले से ही पंजीकरण कर लिया है। बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, कजाकिस्तान, नार्वे, नेपाल, वियतनाम, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, कनाडा सहित भारतीय वायु सेना, सेना और नौसेना के प्रतिभागी भी शामिल होंगे। इन प्रतिभागियों का चयन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन को फेडरेशन ऑफ एयरोनॉटिकल इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप कमीशन और एयरो क्लब इंडिया दोनों से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के दौरान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आर्मी एडवेंचर विंग, भारतीय वायु सेना एडवेंचर विंग के दो दल और समर्पित बचाव टीम भी तैनात की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिगत हेलीकॉप्टर की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बीड़-बिलिंग को देश की पैराग्लाइडिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि आदर्श उड़ान परिस्थितियों और सुन्दर परिदृश्यों के कारण यह क्षेत्र विश्वभर के पैराग्लाइडरों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित कर रही है। इस तरह के आयोजनों से साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बल मिलेगा।

इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, बिलिंग पैराग्लाइडिंग संघ के अध्यक्ष अनुराग शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

सीएम 29 को मंडी में लेंगे अधिकारियों की बैठक

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 29 सितंबर को मंडी में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। इसमें वे मंडी जिले में प्राकृतिक आपदा के नुकसान व उसके उपरांत के राहत-पुनर्वास कार्यो की समीक्षा करेंगे। साथ ही वे पुनर्स्थापन गतिविधियों तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से भविष्य के लिए उठाये कदमों का ब्यौरा भी लेंगे।

जिलाधीश अरिंदम चौधरी ने सभी विभाग प्रमुखों को मुख्यमंत्री की बैठक को लेकर पूरी तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम की समीक्षा बैठक के लिए सभी विभाग नुकसान और राहत-पुनर्वास कार्यो के पूर्ण डाटा के साथ साथ राहत राशि आवंटन के अद्यतन आंकड़े भी रखें। बैठक के लिए बनाई जाने वाली 'पीपीटी' को मुख्यत: 3 पहलुओं पर केंद्रित करें। इसमें नुकसान की जानकारी, राहत-पुनर्वास को लेकर किए कार्यो का ब्यौरा तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से आगे की योजना का उल्लेख करें।

बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा में मंडी जिले को करीब 1600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें प्रमुख रूप से लोक निर्माण विभाग को 437.48 करोड़, जल शक्ति विभाग को 445.03 करोड़, विद्युत बोर्ड को 117.94 करोड़, कृषि को 61.41 करोड़, वन विभाग को 24.15 करोड़, बागवानी को 17.27 करोड़, स्वास्थ्य को 7.81, शिक्षा को 29.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हिमाचल सरकार ने सभी जिलों को राहत-पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन कार्यो के लिए करोड़ों रुपये का अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया है।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त निवेदिता नेगी सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित रहे।

टीबी उन्मूलन तथा एचआईवी से बचाव को आरंभ होगा जागरूकता अभियान

शिमला/शैल। कांगड़ा जिला में टीबी उन्मूलन तथा एचआईबी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान आरंभ किया जा रहा है इसी कड़ी में धर्मशाला के युद्ध संग्रहालय से मेराथॉन का आयोजन किया जाएगा जिसमें युवाओं टीबी उन्मूलन तथा एचआईबी से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे।

सीएमओ डा सुशील शर्मा ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार द्वारा पूरे देश में इन विषयों को लेकर यूथ फेस्ट आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एड्स तथा टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा सरकार के माध्यम से वर्ष भर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं ताकि समाज को विशेषकर युवा वर्ग को जानकारी मिल सके।

उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत ड्रामास्किट, रील मेकिंग और क्विज की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवाओं को पुरस्कृत करने के साथ उन्हें राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह करते हुए कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लें ताकि समाज को टीबी मुक्त बनाया जा सके।

मंडी में देवी–देवताओं के नाम भूमि हस्तांतरण के मामलों में संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर बनी एसओपी

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार मंडी जिला प्रशासन ने जिले में पंजीकृत देवी-देवताओं के मूल स्थानों/मंदिरों के साथ लगती सरकारी/वन भूमि से 10-10 बिस्वा भूमि मांग के अनुरूप देवी-देवता के नाम करने के मामलों में एक सुस्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए सर्व देवता समिति मंडी के साथ बैठक की। बैठक में व्यापक विचार विमर्श के उपरांत भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों एवं मामलों में समिति की सहमति से आवेदन से स्वीकृति तक की संपूर्ण प्रक्रिया को लेकर एसओपी तय की गई।

इसके अलावा बैठक में प्रशासन को अब तक प्राप्त ऐसे विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

डीसी अरिंदम चौधरी ने उपमंडलवार प्राप्त मामलों पर विस्तार से चर्चा की और वस्तुस्थिति का ब्यौरा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिले में मांग के अनुरूप देवी देवताओं के मूल स्थानों/मंदिरों के साथ लगती सरकारी/वन भूमि से 10-10 बिस्वा भूमि देवी-देवता के नाम करने को लेकर एक सुस्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारण के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में सर्व देवता समिति के साथ चर्चा की गई ताकि किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। ऐसे मामलों में आवेदन से लेकर स्वीकृति तक की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एसओपी तय की गई है।

उन्होंने आग्रह किया कि भूमि के लिए आवेदन करते समय यह ध्यान में रखें कि मंदिर के साथ लगती जमीन रिक्त भूमि हो और वहां पर पहले से कोई निर्माण न हुआ हो। उन्होंने कहा कि वन भूमि से जुड़े मामलों में एफआरए स्वीकृति के केस बना कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

मंडी शिवरात्रि को लेकर 216 देवी देवता पंजीकृत हैं। सुंदरनगर शिवरात्रि में 65 देवी देवता पंजीकृत हैं। प्रशासन को नए पंजीकरण के लिए भी आवेदन प्राप्त होते रहते हैं। बैठक में सर्व देवता समिति के अध्यक्ष शिव पाल शर्मा और अन्य समिति सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

एडीएम डॉ. मदन कुमार ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। इस दौरान सर्व देवता समिति के प्रतिनिधियों के अलावा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

आयुष्मान योजना के तहत कांगड़ा जिला में पंजीकृत हुए 92264 परिवार

शिमला/शैल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पांच वर्ष पूर्ण होने पर कांगड़ा जिला में 23 सितंबर को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह जानकारी सीएमओ सुशील शर्मा ने देते हुए बताया कि इस योजना के तहत कांगड़ा जिला में 92264 परिवार पंजीकृत हैं इस योजना के तहत कांगड़ा जिला में 2 लाख 43 हजार 862 लाभार्थी लाभ उठा चुके हैं।

इस योजना के तहत साठ करोड़ की राषि व्यय की गई है। वर्तमान में कांगड़ा जिला में 55 पंजीकृत अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत आयुष्मान भारत हेल्थ अकांउट भी बनाये जा रहे हैं जिस के लिए लाभार्थी अपने साथ आधाार काड़ लेकर नजदीकी हेल्थ वेलनेस सेंटर में जाकर अपना हेल्थ अकाउंट बनवा सकते हैं ताकि उन्हें अपनी हेल्थ की सभी जानकारियां हेल्थ अकाउंट के माध्यम से मिल सकें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सभी छूटे हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियें से अनुरोध किया है कि वह अपने आयुष्मान कार्ड स्वयं अपने नजदीकी आशा वर्कर या लोक मित्र केन्द्र या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपने हेल्थ कार्ड जल्द से जल्द बनवा लें। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान एप 1.4 डाउनलोड कर ऑनलाइन स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।

आपदा में डियूटी से कन्नी काटने वालों पर कड़ी कारवाई की तैयारी

शिमला/शैल। मंडी जिले में बीते दिनों प्राकृतिक आपदा के दौरान जहां अनेक अधिकारी-कर्मचारी दिन रात एक कर आपदा प्रबंधन में डटे रहे, वहीं कुछ इने-गिने अधिकारी-कर्मचारी ऐसे भी थे जो इन विकट परिस्थितियों में बिना वाजिब वजह बताये डियूटी से नदारद रहे। अब मंडी जिला प्रशासन आपदा में डियूटी से कन्नी काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जिला प्रशासन ने आपदा के समय डियूटी से नदारद रहे बालीचौकी उपमंडल के विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी मंडी डॉ. मदन कुमार ने कहा कि आपदा के समय में जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों ने लोगों की सुरक्षा और उन्हें राहत देने के लिए बहुत हिम्मत और जज्बे से काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी संज्ञान में आये हैं जिनमें विकट समय में कुछ अधिकारी-कर्मचारी बिना किसी सूचना के अपनी डियूटी से नदारद रहे। प्रशासन ने ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आपदा के समय में अपने कर्तव्य का सही पालन न करने और कोताही के कारण आपदा प्रबंधन में कठिनाई तो होती ही है, साथ ही अव्यवस्था का आलम भी बनता है। वहीं इससे जी-जान से काम करने वाले लोगों का हौंसला भी टूटता है।

प्रशासन ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे बिना पूर्व जानकारी दिए डियूटी से गायब रहने का कारण पूछा है। संतोषजनक उत्तर न मिलने की स्थिति में उनके खिलाफ आगे नियमानुसार कारवाई की जाएगी।

महिलाओं को दिया डेयरी फॉर्मिंग का प्रशिक्षण

शिमला/शैल। पंजाब नैंशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण सस्थान धर्मशाला द्वारा बेरोजगार युवक एवं युवतियों को स्वरोजगार की ओरअग्रसर करने के लिए डेयरी फॉर्मिंग एवं केचुआ खाद बनाने का दस दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर निदेशक पी.एन.बी.आरसेटी गरिमा, आर.सेटी हि. प्र. की राज्य सहायक नियंत्रक डा. अम्बिका साहु, डोमेन एसेसर कुदन लाल, प्रशिक्षुओं का मागदर्शन किया। इस अवसर पर आर.सेटी निदेशक गरिमा ने बताया कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर मे जिला कांगडा के गाव कण्डबाड़ी की 34 महिला प्रशिक्षणाथियों ने भाग लिया जिसमें विभिन्न तरह की स्किल डेवलपमेंट के साथ डेयरी फॉर्मिंग एवं केचुआ खाद बनाने के बारे मे विस्तार से सीखा ताकि स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें।

उन्होंने बताया कि पंजाब नैंशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण सस्थान धर्मशाला भविष्य में कृत्रिम आभूषण बनाने का 13 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, ब्युटी पार्लर का तीस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर तथा मधुमक्खी पालन दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आरंभ करेगा उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवक एवं युवतियां नजदीक गर्वमेंन्ट कॉलेज ओडिटोरियम सिविल लाईन धर्मशाला, पी. एन. बी. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कांगड़ा मे सम्पर्क कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के निदेशक गरिमा से उनके दूरभाष नंबर 9418883050 एवं आफिस नंबर 9459900660 पर संपर्क कर सकते है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

वित्तीय श्वेत पत्र झूठ का पुलिंदा-जयराम

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा सदन में रखे गये वित्तीय श्वेत पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुये इसमें दिखाये गये कुछ आंकड़ों को भी गलत कहा है। जयराम ने कहा कि प्रदेश में वित्तिय कुप्रबन्धन की शुरुआत 1993 से 1998 तक रही कांग्रेस सरकार के समय हुई थी। जब बिजली बोर्ड और कुछ निगमों के नाम पर खुले बाजार में से एक हजार करोड़ का कर्ज लिया गया था जो उस समय सबसे अधिक था और आगे चलकर वह वित्तीय बोझ बनता चला गया। जबकि इस ऋण की उस समय इतनी आवश्यकता नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब 2012 में भाजपा ने सरकार छोड़ी थी तब प्रदेश पर 28000 करोड़ की देनदारी थी। लेकिन जब 2017 में उन्होंने सत्ता संभाली तो उन्हें 48000 करोड़ का ऋण विरासत में मिला जो कि 66% की बढ़ौतरी थी। ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया कि जब उन्होंने सत्ता छोड़ी तो उस समय 69622 करोड़ के कुल कर्ज था 75000 करोड़ का नहीं। जयराम ने यह भी स्पष्ट किया कि इन्वैस्टर मीट के लिये 10 करोड़ केंद्र ने दिया था। और दो बार 13000 तथा 28000 करोड़ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुये थे। जिनमें से 8000 करोड़ के उद्योग शुरू भी हो चुके हैं। इसी कड़ी में जयराम ने मुकेश अग्निहोत्री से यह भी पूछा कि जब वह उद्योग मंत्री थे तब कितने एम. ओ.यू. साइन हुये थे और कितने धरातल पर साकार हुये है। जयराम ने आरोप लगाया कि यह सरकार नौ माह के कार्यकाल में ही 8000 करोड़ का ऋण ले चुकी है। जिस तरह से श्वेत पत्र केवल एक ही सरकार के कार्यकाल को लेकर लाया गया है तो वह निश्चित रूप से श्वेत पत्र की जगह आरोप पत्र हो जाता है। ऐसे में अपने पर लग रहे आरोपों का पुरजोर खण्डन करना स्वभाविक हो जाता है। लेकिन जिस तरह की कार्य प्रणाली पिछले नौ माह में इस सरकार की रही है उसको लेकर प्रश्न उठना स्वभाविक है क्योंकि यह सरकार दस गारंटीयां देकर सत्ता में आयी है। उन गारंटीयों पर व्यवहारिक रूप से अभी कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। गारंटीयां जारी करते हुये यह नहीं कहा गया था कि पांच वर्ष के कार्यकाल में इनको पूरा किया जायेगा। इसलिए जयराम ने अपनी पत्रकार वार्ता में मुकेश अग्निहोत्री का ही ब्यान प्ले करके सुनाया है। जयराम सरकार के कार्यकाल के अन्तिम छः माह में लिये गये फैसलों को पलटते हुये इस सरकार ने करीब एक हजार संस्थाओं को बन्द कर दिया है। जब सुक्खू सरकार ने संस्थान बन्द करने का फैसला लिया तभी इस मुद्दे को भाजपा पूरे प्रदेश में ले गयी थी। इससे कांग्रेस के लोग भी घिर कर रह गये हैं क्योंकि उनके क्षेत्रों में भी यह संस्थान खुले थे। इसलिये इस संबंध में यह सरकार दो टूक फैसला नहीं ले पा रही है। भाजपा इस मुद्दे को प्रदेश उच्च न्यायालय में भी ले जा चुकी है। इसी मुद्दे के साथ मुख्य संसदीय सचिवों का मुद्दा भी अदालत में चल रहा है। अब श्वेत पत्र पर पलटवार करते हुये जो आंकड़े जयराम ने उठाये हैं वह सब 8 मार्च 2018 को विधानसभा में आये उनके बजट भाषण में दर्ज हैं। कांग्रेस इन कर्ज के आंकड़ों पर आज तक जवाब नहीं दे पायी है। इसलिये अब एक ही सरकार के कार्यकाल को लेकर लाये गये श्वेत पत्र पर सवाल उठना स्वभाविक ही है। क्योंकि जिस अफसरशाही ने सरकार को आंकड़े पढ़ाये हैं उसी ने ही विपक्ष को भी परोसे हैं। ऐसे में नौ माह में ही 8000 करोड़ का कर्ज ले लेना और गारंटीयों पर अमल कर पाना आसान नहीं होगा। श्वेत पत्र पर उठी यह बहस लोकसभा चुनाव तक क्या शक्ल लेती है यह देखना दिलचस्प होगा।

- नौ माह में ही 8000 करोड़ का कर्ज लेना अपने में ही एक बड़ा सवाल है
- गारंटीयों पर अब लोग सवाल करने लग पड़े हैं

तीन वर्षों से नहीं आयी उच्च शिक्षा विनियामक आयोग की रिपोर्ट

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार में प्राइवेट सैक्टर में खुले उच्च शिक्षण संस्थानों को रैगुलेट करने के लिये 2010 में एक विनियामक आयोग की स्थापना की थी। हॉयर एजुकेशन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना as per the notification the Commission shall prepare and submit the annual report to the Government as required under the provision of section 13 of the Act, giving true and full account of the activities undertaken during the previous year. के अनुसार यह आयोग हर वर्ष अपनी वर्ष भर की गतिविधियों को लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा। यह रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर भी रखी जाती है। आयोग की वेबसाइट पर भी लोड की जाती है। तथा आर.टी.आई. के तहत भी उपलब्ध रहती है। वर्ष 2019 तक यह रिपोर्ट बराबर प्रकाशित होती रही है। लेकिन उसके बाद आज तक यह रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। इस संबंध में जब भी आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगी गयी तो एक ही जवाब मिला की रिपोर्ट तैयार हो रही है। स्मरणीय है कि यह विनियामक आयोग इसलिये स्थापित किया गया था ताकि निजी क्षेत्र में खुले उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों और उनके अभिभावकों का शोषण न हो। वहां हो रहा शिक्षण और वहां तैनात सारा स्टाफ वॉइस चांसलर से लेकर नीचे तक तह मानकों के तहत भर्ती किया गया हो। पिछले दिनों जब मानव भारती विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ी सामने आयी है तब से इस आयोग की कार्य प्रणाली और भी महत्वपूर्ण हो गयी है। कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। यहां तक आशंकाएं व्यक्त की गई है कि इन संस्थान में कई विषयों के लिये इतनी-इतनी सीटें दे दी जाती है जो सरकार क्षेत्र में दशकों से खुले शिक्षण संस्थानों को भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। सीटें देना और तय मानकों की अनुपालन सुनिश्चित करवाना यह सब इस आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह आशंकाएं व्यक्त की जा रही है की कुछ विश्वविद्यालयों को कई कोर्सो में इतनी अधिक सीटें दे दी गई है जिनके वह शायद पात्र ही नहीं थे। इसमें शूलिनी विश्वविद्यालय तक नाम उछल रहा है।

Please refer to RTI application dated 07.11.2022 received in this Commission on 10.11.2022 for seeking information under RTI Act, 2005. Wherein the information sought is as under:

Sr. No.	Information Sought	Information Available/Remarks
1.	Please provide me the copy of annual report of year 2021-22 of HP-PERC.	Preparation of report is still under process.

If you are not satisfied with the information given, you may file appeal to the Chairman, HP-PERC, whose contact address is as under:

The Chairman-cum- 1st Appellate Authority, HP-PERC, Happy Nest Building, Phase –III, Below BCS, Kagnadhar, Shimla-9

Yours faithfully,

PIO-cum-Secretary
H.P. Private Educational Institutions
Regulatory Commission